University in News on 15 February 2025

AMAR UJALA MY CITY PAGE 7

लविवि: नए कॉलेजों, कोर्स की मान्यता के 28 तक आवेदन

अधिसूचना जारी, कुलसचिव कार्यालय में कर सकते हैं आवेदन

संवाद न्यूज एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय से नए महाविद्यालयों की संबद्धता और पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मान्यता हासिल करने के आवेदन शुरू हो गए हैं। महाविद्यालय प्रशासन निरीक्षण मंडल के गठन के लिए 28 तक कुलसचिव कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

कुलसचिव विद्यानंद त्रिपाठी की ओर से शुक्रवार को वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। पत्र में कहा गया कि जिन महाविद्यालयों ने नए कोर्स या पूर्णकालिक मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है, वे तय तिथि में ऐसा कर दें।

मान्यता के संबंध में विवि का निरीक्षण मंडल गठन करने की अंतिम तिथि 10 मार्च, निरीक्षण मंडल के निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पांच अप्रैल, विवि के ऑनलाइन संबद्धता देने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल, शासन में अपील करने की अंतिम तिथि 10 मई होगी। शासन स्तर से अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि 31 मई होगी।

कुलसचिव ने कहा, लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर और लखीमपुर के जिन कॉलेजों की मान्यता 30 जून को समाप्त हो रही है, वे आगामी सत्र के लिए आवेदन निरीक्षक मंडल से प्राप्त कर लें। ऐसा न करने पर सत्र 2025-26 में प्रवेश प्रतिबंधित रहेंगे।

आईक्यूएसी समिति का पुनर्गठन

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) का पुनर्गठन किया गया है। कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय इसके चेयरमैन होंगे। 21 लोगों को इसका सदस्य बनाया गया है। कुलसचिव विद्यानंद त्रिपाठी इसका आदेश जारी कर दिया है। (संवाद)

जमा करना होगा शुल्क

- कुलसचिव ने बताया कि स्थलीय निरीक्षण मंडल नामित करने के लिए आवेदक लविवि के खाते में नए कोर्स के लिए 35,400 रुपये शुल्क जमा कर दें। नवीन महाविद्यालय संचालन की सहयुक्तता के लिए शुल्क 59,000 रुपये लगेंगे। आवेदन पत्र के साथ सहयुक्ता व अनापत्ति की सत्यापित प्रतिलिपि भी कुलसचिव कार्यालय में जमा करनी होगी।

कर्मयोगी छात्रवृत्ति के लिए 32 मेधावियों का चयन

कर्मयोगी छात्रवृत्ति के लिए चयनित विद्यार्थियों के साथ कुलपति व अन्य। स्रोत : लविवि

संवाद न्यूज एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में शुक्रवार को कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने कर्मयोगी छात्रवृत्ति के 32 चयनितों को प्रमाणपत्र दिए। ये विद्यार्थी हर कार्य दिवस पर पढ़ाई के साथ विवि के कार्यालयों में दो घंटे सेवाएं देंगे।

इसके लिए उन्हें 150 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से विवि पारिश्रमिक देगा, जो अधिकतम 50 घंटे के लिए होगा।

प्रवक्ता प्रो. दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि विश्वविद्यालय हर साल मेधावी विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देता है। ये वे विद्यार्थी होते हैं, जो आर्थिक तौर पर कमजोर होते हैं। विश्वविद्यालय इन्हें काम के अनुभव के साथ पारिश्रमिक देता है, जिससे वे आसानी से शिक्षा पूरी कर सकें।

हर साल शोध मेधा, छात्रकल्याण छात्रवृत्ति के साथ इसके लिए आवेदन लिए जाते हैं। यह छात्रवृत्ति पाने की पहली शर्त यह है कि विद्यार्थी किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ न ले रहा हो।

पढ़ाई के साथ लविवि के कार्यालयों में 50 घंटे तक देंगे सेवा

150 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से विश्वविद्यालय देगा पारिश्रमिक

HINDUSTAN PAGE 8

लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग की ओर से राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार

कृषि, एमएसएमई, निवेश व निर्यात देश के विकास इंजन: पंकज चौधरी

आयोजन

लखनऊ, संवाददाता। लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग की ओर से एपी सेन सभागार में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर विजन विकसित भारत@2047 विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार हुआ।

मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से देश के बहुमुखी विकास में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात देश के विकास इंजन हैं।

कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने कहा कि कंपनियां राष्ट्र की प्रगति में प्रमुख हितधारक हैं। सतत विकास की परियोजनाओं के संचालन में कॉर्पोरेट जगत से सहयोग की उम्मीद है। यह बौद्धिक विमर्श विकसित भारत का ब्लूप्रिंट प्रस्तुत कर रहा है। यह विचार-विमर्श नीति निर्धारण में सहायक होंगे।

लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मुख्य अतिथि रहे।

02 दिवसीय सेमिनार का एपी सेन सभागार में आगाज

258 शोधपत्रों का सेमिनार में किया गया विमोचन

- प्रोफेसर मनोज अग्रवाल की पुस्तक इंडियन इकोनॉमी का विमोचन
- विजन विकसित भारत@2047 विषय पर सेमिनार का आयोजन

इस दौरान सेमिनार की स्मारिका, 258 शोधपत्र, प्रोफेसर मनोज अग्रवाल की पुस्तक इंडियन इकोनॉमी का विमोचन किया गया। डॉ. हरनाम सिंह, डॉ. शची राय, प्रो. विनोद कुमार सिंह, प्रो. राकेश द्विवेदी, प्रो. वीके शर्मा, प्रो. एमएम वर्मा, प्रो. पंकज माथुर, प्रो. अनूप सिंह, प्रो. मंजुला उपाध्याय, प्रो. मनोज शर्मा, डॉ. अनित्य गौरव, प्रो. ओमकार, डॉ. पारुल जैन, प्रो. रोली मिश्रा, प्रो. अशोक कुमार कैथल, प्रो. मधुरिमा लाल, प्रो. शीतल, प्रो. संगीता समेत अन्य मौजूद रहे।

मान्यता के लिए आवेदन 28 फरवरी तक

लखनऊ विश्वविद्यालय से नए कॉलेजों की संबद्धता और पाठ्यक्रम संलालन के लिए मान्यता हासिल करने के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। महाविद्यालय प्रशासन निरीक्षण मंडल के गठन के लिए 28 फरवरी तक एलयू के कुलसचिव कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में कुलसचिव विद्यानंद त्रिपाठी की ओर से वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर दी गई है।

छात्रवृत्ति के लिए चयनित छात्रों को प्रमाण पत्र मिले

लखनऊ विश्वविद्यालय में शुक्रवार को कर्मयोगी छात्रवृत्ति के लिए चयनित विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे गए। मंथन हॉल में कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने 32 मेधावियों को प्रमाण पत्र दिए। कर्मयोगी छात्रवृत्ति के लिए चयनित यह सभी विद्यार्थी प्रत्येक कार्य दिवस में पढ़ाई के साथ ही एलयू के विभिन्न कार्यालयों में दो घंटे सेवाएं देंगे।

लवि कुलपति प्रो. आलोक राय ने कर्मयोगी छात्रवृत्ति के लिए चयनित मेधावियों को प्रमाण पत्र दिए • लवि

32 मेधावियों को दिया छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र

जासं • लखनऊ : लवि के मंथन हाल में शुक्रवार को कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने सत्र 2024-25 के लिए कर्मयोगी छात्रवृत्ति के लिए चयनित छात्र-छात्राओं को प्रमाण-पत्र वितरित किया। इसमें विभिन्न विभागों एवं संकायों से 32 मेधावियों को प्रमाण पत्र मिला। इस अवसर पर प्रति कुलपति प्रो. मनुका खन्ना, डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रो. वीके शर्मा, चीफ प्रोवोस्ट प्रो. अनूप कुमार सिंह, डीन प्रवेश प्रो. पंकज माथुर, निदेशक आइपीपीआर प्रो. दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव उपस्थित रहे। यह छात्रवृत्ति लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययनरत मेधावी विद्यार्थियों को हर साल दी जाती है। इसमें चयनित विद्यार्थी को विभागों में कार्य करने के बदले में 150 रुपये प्रति घंटे (रोज दो घंटे) दिए जाते हैं।

JAGRAN CITY PAGE III

लवि : 15 नए कालेजों, 102 कोर्सों को मिली एनओसी

जासं • लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय ने राजधानी सहित चार अन्य जिलों में 15 नए डिग्री कालेजों के साथ-साथ 102 नवीन पाठ्यक्रमों एवं विषयों के संचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर दिया है। अब इन कालेजों को नए सत्र से संचालन के लिए 28 फरवरी तक आनलाइन माध्यम से लवि में सहयुक्तता के लिए आवेदन करना होगा। विश्वविद्यालय की ओर से गठित पैनल संबंधित कालेजों में जाकर सुविधाओं व अन्य मानकों की जांच कर अपनी रिपोर्ट देगा। इसके बाद लवि सहयुक्तता देगा।

लवि से संबद्ध लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, लखीमपुर खीरी और हरदोई में करीब 545 महाविद्यालय संचालित हैं। नए सत्र में इसकी संख्या और बढ़ेगी। बीते दिनों शासन के आदेश पर नए कालेजों और कोर्सों के संचालन के लिए आवेदन किए गए थे, जिसके बाद नियमों के अनुसार 117 एनओसी जारी की गई हैं। इनमें 15 नए प्राइवेट कालेज और पूर्व में चल रहे कालेजों में स्नातक व परास्नातक स्तर के 102 नवीन कोर्स एवं विषय संचालन के लिए मंजूर किए गए हैं। कुलसचिव नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी ने बताया कि जिन्हें एनओसी मिल गई है, उन्हें सहयुक्तता की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

राजधानी के चार एडेड कालेजों को नवीन कोर्स एवं विषय शुरू करने के लिए एनओसी मिल गई है। शिया कालेज में बी.काम आनर्स और एलएलएम पाठ्यक्रम शुरू होगा। मीडिया प्रभारी डा. प्रदीप शर्मा ने बताया कि सहयुक्तता के लिए प्रक्रिया पूरी की जाएगी। खुन खुन जी गर्ल्स कालेज, चौक में एम.ए समाजशास्त्र कोर्स की एनओसी मिल गई है। प्राचार्य प्रो. अंशु केडिया के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी कर कोर्स शुरू किया जाएगा। केकेसी के प्राचार्य प्रो. विनोद चंद्र ने बताया कि एम.एसएससी गणित, एम.एसएससी जंतु विज्ञान, बीसीए, एल.एल.बी पांच वर्षीय और स्नातक में भूगोल व मनोविज्ञान विषय की एनओसी मिल गई है।

28 फरवरी तक कर सकेंगे सहयुक्तता के निरीक्षण मंडल के लिए आनलाइन आवेदन

सीएसआर फंड की पूरी रकम नहीं खर्च कर रहीं कंपनियां

लविवि के अर्थशास्त्र विभाग के राष्ट्रीय सेमिनार में प्रस्तुत शोध पत्र में दावा

संवाद न्यूज एजेंसी

लखनऊ। देश में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) फंड में कंपनियां पूरी रकम खर्च नहीं कर रही हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के मुताबिक वर्ष 2014 से 2023 तक इस फंड में 2.50 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाने थे, लेकिन 1.84 हजार करोड़ रुपये ही खर्च किए गए।

सेमिनार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी।

इतना ही नहीं खर्च न होने वाली 65 हजार करोड़ रुपये की रकम का कोई हिसाब भी नहीं है। यह दावा गिरि अध्ययन संस्थान में प्रोजेक्ट सलाहकार डॉ. संदीप बालियान ने किया है।

वह शुक्रवार को लविवि के अर्थशास्त्र विभाग की ओर से एपीसेन सभागार में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल्स फॉर विजन विकसित भारत@2047 में शोधपत्र प्रस्तुत कर रहे थे।

उन्होंने कहा, सरकार को यह रकम सामाजिक हित में खर्च करवाने के लिए निगरानी सघन करनी होगी। दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने किया। उन्होंने कहा, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से देश के विकास में सराहनीय कार्य किया जा रहा है सरकार ने कर प्रणाली में सुधार करके व्यापार को आसान बनाया है। हमें आत्मनिर्भर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है।

कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने कहा कंपनियां राष्ट्र की प्रगति में प्रमुख हितधारक हैं यह बौद्धिक विमर्श विकसित भारत क ब्ल्यूप्रिंट प्रस्तुत कर रहा है। यह विचार-विमश नीति निर्धारण में सहायक होंगे।

कार्यक्रम में सेमिनार की स्मारिका, 258 शोधपत्र, प्रो. मनोज अग्रवाल की पुस्तक इंडियन इकोनॉमी का विमोचन किया गया अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रो. विनोद कुमार सिंह, डॉ. हरनाम सिंह, डॉ शची राय, प्रो राकेश द्विवेदी, वीके शर्मा, प्रो. एमएम वर्मा, प्रो. पंकज माथुर, प्रो. अनूप सिंह, प्रो. मंजुला उपाध्याय आदि की उपस्थिति रही।

क्या है सीएसआर फंड

सीएसआर का मतलब कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है। इसका मकसद किसी कंपनी को समुदाय और हितधारकों के प्रति सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाना है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत हर कंपनी को अपने शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत हिस्सा सीएसआर मद में खर्च करना होता है।

i-NEXT PAGE 2

सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कॉर्पोरेट अहम

पंकज चौधरी बोले, आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत बनेगा विकसित राष्ट्र

LUCKNOW (14 FEB): कार्पोरेट हाउस देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसके साथ ही सस्टेनेबल डेपलवमेंट में भी कार्पोरेट का रोल अहम है. पीएम मोदी के विजन विकसित भारत 2047 को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर विचार-विमर्श करने के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में दो दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन शुक्रवार को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने किया.

PIC: DAINIK JAGRAN-I NEXT

साथ मिलकर करें काम

इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री ने पीएम के विजन के बारे में बात करते हुए कहा कि विकसित भारत की संकल्पना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, डिजिटल क्रांति, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरमेंट टल सस्टेनेबिलिटी पर एक साथ काम करने से पूरा होगा और यह काम सरकार और कॉर्पोरेट को साथ मिलकर करना होगा. सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे विवि के वीसी प्रो. आलोक कुमार राय ने कहा कि विकसित भारत 2047 की संकल्पना को साकार करने के लिए ही विश्वविद्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें विचार-विमर्श कर विकसित भारत का एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा.

बुक का भी हुआ विमोचन

इस सेमिनार में ही इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के वरिष्ठ प्रोफेसर एमके अग्रवाल की बुक इंडियन इकोनॉमी का भी विमोचन किया गया. सेमिनार का संचालन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. हरनाम सिंह ने किया. इस मौके पर वीके शर्मा, एमएम वर्मा, प्रो. पंकज माथुर, प्रो. अनूप कुमार सिंह, प्रो. मंजुला उपाध्याय, प्रो. मनोज शर्मा, प्रो. अनित्य गौरव सहित विवि के कई प्रोफेसर, रिसर्च स्टूडेंट्स मौजूद रहे.

PIONEER PAGE 3

देश की स्वतन्त्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत विकसित राष्ट्र होगा: पंकज चौधरी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचा, डिजिटल क्रांति और पर्यावरणीय स्थिरता पर सम्यक रूप से कार्य करने से साकार होगा। यह संतुलन सरकार और कॉर्पोरेट जगत को मिलकर साधना होगा। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से देश के बहुमुखी विकास में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। सार्वजनिक-निजी साझेदारी के साथ सरकार कार्य कर रही है, जिससे देश विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में अग्रसर हो सके। चौधरी शुक्रवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। एपी सेन हॉल में आयोजित नेशनल सेमीनार कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फार विज़न विकसित भारत-2047 पर बोलते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने कर प्रणाली में सुधार करके व्यापार को आसान बनाया है। हमें आत्मनिर्भर विकसित भारत की संकल्पना साकार करना है। केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री संकल्पबद्ध है 2047 तक देश को एक विकसित, आत्मनिर्भर और वैश्विक नेतृत्व करने वाला देश बनाने की। विकसित राष्ट्र के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवनशैली जैसी मूलभूत जरूरतों पर सरकार का फोकस है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीति आयोग ने 2030 तक का समय निर्धारित किया है।

'कर प्रणाली में सुधार से व्यापार आसान'

कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फार विजन विकसित भारत राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन

जागरण संवाददाता • लखनऊ : केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचा, डिजिटल क्रांति व पर्यावरणीय स्थिरता के लिए निरंतर कार्य करने से विकसित भारत की संकल्पना साकार होगी। कारपोरेट जगत सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से देश के बहुमुखी विकास में सराहनीय योगदान दे रहा है। सार्वजनिक-निजी साझेदारी के साथ सरकार कार्य कर रही है ताकि देश विश्व का अग्रणी राष्ट्र बन सके। सरकार ने कर प्रणाली में सुधार करके व्यापार को आसान बनाया है, अब सबको आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाना है। वह शुक्रवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के एपी सेन सभागार में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य अतिथि शामिल हुए।

दो दिवसीय 'कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फार विजन विकसित भारत' सेमिनार का उद्घाटन करके केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री चौधरी ने कहा, विकसित राष्ट्र के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवनशैली जैसी मूलभूत जरूरतों पर सरकार का फोकस है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीति आयोग ने 2030 तक का समय निर्धारित किया है। उन्होंने कहा, आयुष्मान भारत देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। सेमिनार के विचार मंथन के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसकी सिफारिशें सरकार के संबंधित मंत्रालयों को भेजिए, उन्हें लागू कराएंगे।

निजी कंपनियां राष्ट्र की प्रगति का प्रमुख आधार : सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे लवि के कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने कहा, निजी कंपनियां राष्ट्र की प्रगति का प्रमुख आधार हैं। सतत विकास की परियोजनाओं के संचालन में कारपोरेट जगत से सहयोग की आकांक्षा है। विश्वविद्यालय विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए दो दिवसीय विचार-विमर्श कर विकसित भारत के लिए एक ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करेगा, जो नीति निर्धारण में तो सहायक होंगे। कला संकायाध्यक्ष प्रो. अरविंद मोहन ने कहा, हम सब मिलकर 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के अपने दायित्वों का निर्वहन करें। सेमिनार संयोजिका डा. शची राय ने सेमिनार की प्रस्तावना व अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रो. विनोद सिंह ने आभार जताया।

प्रो. एमके अग्रवाल की पुस्तक का हुआ विमोचन : केंद्रीय मंत्री ने अर्थशास्त्र विभाग के वरिष्ठ प्रो एमके अग्रवाल की पुस्तक इंडियन इकोनोमी का विमोचन किया। इस अवसर पर 258 शोधपत्रों के सार वाली स्मारिका का भी विमोचन हुआ।

लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित सेमिनार में प्रो. एमके अग्रवाल की पुस्तक इंडियन इकोनोमी का विमोचन करते केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, साथ में कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय, प्रो. अरविन्द मोहन, डा. शची राय व प्रो. विनोद सिंह • जागरण

AMRIT VICHAR PAGE 4

आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर विकसित बनेगा देश

वित्त राज्यमंत्री ने कहा, अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने के लिए काम कर रही सरकार

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार: कुछ वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। बजट इसी दिशा में कार्य करेगा। आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचा, डिजिटल क्रांति और पर्यावरणीय स्थिरता पर कार्य करते हुए आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। इसके लिए सरकार और कॉर्पोरेट जगत को मिलकर कार्य करना होगा। ये बात केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद कही।

विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग ने राष्ट्रीय सेमिनार कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फार विज़न विकसित भारत पर कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक और निजी साझेदारी के साथ कार्य कर रही है, जिससे देश दुनिया का नेतृत्व कर सके। आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवनशैली जैसी मूलभूत जरूरतों पर सरकार का फोकस है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीति आयोग ने 2030 तक का समय निर्धारित किया है। इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत तथा प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसे कई कार्यक्रमों के माध्यम से हम लगातार आर्थिक समावेशन और मानव विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।

पुस्तक का विमोचन करते पंकज चौधरी, कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय और अन्य।

▸▸ बोले, विकसित भारत के लिए सरकार व कॉर्पोरेट जगत को मिलकर करना होगा कार्य

स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड

नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स को 10,000 करोड़ रुपये व्यवस्था की गई है। बुनियादी ढांचे के विकास और कुशल कनेक्टिविटी के माध्यम से नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

दुनिया में यूपीआई क्रांति की चर्चा

सरकार अर्थव्यवस्था को डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलने का प्रयास कर रही हैं। विश्व में भारत के यूपीआई क्रांति की चर्चा है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को यूपीआई-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। परमाणु ऊर्जा मिशन जैसी पहले देश में वैज्ञानिक प्रोत्साहन एवं तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दे रही है। भारतट्रेडनेट (BTN) के रूप में एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है।

आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना

वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है जिससे 50 करोड़ से अधिक लोग सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। नए और छोटे उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब 20 लाख तक के लोन को कोलैटरल फ्री कर दिया गया है। इस बार के बजट में भी सरकार आत्मनिर्भर, समावेशी और सतत विकसित भारत कि प्रतिबद्धता है। बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों एवं महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह बजट कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात जैसे चार प्रमुख ग्रोथ इंजन पर केंद्रित है।

VoL PAGE 6

प्रो. आलोक राय ने बांटे कर्मयोगी छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के मंथन हॉल में कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने सत्र 2024-25 के लिए कर्मयोगी छात्रवृत्ति के लिए चयनित छात्र-छात्राओं को प्रमाण-पत्र वितरित किया गया। जिसमें विभिन्न विभागों एवं संकायों से कुल 32 मेधावियों को प्रमाण पत्र दिया गया। यह छात्रवृत्ति लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययनरत मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। प्रमाण पत्र वितरण समारोह में प्रति कुलपति प्रो. मनुका खन्ना, डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रो. वीके शर्मा, चीफ प्रोवोस्ट प्रो. अनूप कुमार सिंह, डीन प्रवेश प्रो. पंकज माथुर, निदेशक आईपीपीआर प्रो. दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव और डीएसडब्ल्यू टीम के समस्त सदस्य उपस्थित रहे।

TOI PAGE 7

University of Lucknow
(Accredited A++ by NAAC)
Lucknow

Advertisement No. R/01/25 चि0अ0 — **Advertisement** — Date 03.02.2025

Online Applications are invited from Indian Citizens for the vacant Posts of Resident Medical Officers in the University. The details and submission of application form is available on **https://lkounivnt.samarth.edu.in/** on CAREERS menu of the university website www.lkouniv.ac.in. **Last date for submission of Online Application Form is 28.02.2025.**

Registrar

NBT PAGE 7

University of Lucknow
(Accredited A++ by NAAC)
Lucknow

Advertisement No. R/01/25 चि0अ0 — **Advertisement** — Date 03.02.2025

Online Applications are invited from Indian Citizens for the vacant Posts of Resident Medical Officers in the University. The details and submission of application form is available on **https://lkounivnt.samarth.edu.in/** on CAREERS menu of the university website www.lkouniv.ac.in. **Last date for submission of Online Application Form is 28.02.2025.**

Registrar